भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1484
दिनांक 29 जुलाई, 2025/07 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

उच्च जोखिम वाले सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचा

†1484. श्री सुखजिंदर सिंह रंधावाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बमियाल, कलानौर और डेरा बाबा नानक जैसे उच्च जोखिम वाले सीमावर्ती गांवों में नागरिक बुनियादी ढांचे की स्थिति का आकलन करने के लिए कोई संपरीक्षा या क्षेत्र सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो विशेष रूप से अग्रिम चौकियों तक सड़कों, आघात देखभाल की उपलब्धता और ग्रामीण स्कूलों की गोलाबारी से सुरक्षा के संबंध में ऐसे आकलन के निष्कर्ष क्या रहे; और

(ग) क्या सरकार इन संवेदनशील क्षेत्रों में विकास पहलों को सुरक्षा संभार के साथ समन्वित करने के लिए एक संयुक्त बीएसएफ-बीएडीपी समन्वय समिति गठित करेगी?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): स्थानीय बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। हालांकि, भारत सरकार भारत-पाकिस्थान सीमा पर स्थित गांवों सहित सीमावर्ती गांवों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इन क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें उनके व्यापक विकास के लिए एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रुप में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-।। भी शामिल है।

(ग): भारत-पाकिस्तान सीमा की बस्तियों के लिए सीमा रक्षक बलों (बीजीएफ) जिसमें सीमा सुरक्षा बल (BSF) भी शामिल है, का समन्वय राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और जिला अधिकारीयों के साथ मौजूदा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) की दिशानिर्देशों में परिभाषित है।

*****